Mr. Speaker: What to do; I am not able to help it (*Interruptions*).

Shri Shri Chand Goel: Could you tell us where the front ends and from where the back benches start?

Shri S. Kundu: Sir, I rise to a point of order. Those who sit in the back would definitely not like to be called back-benchers. It would be better if you call us "those who sit slightly behind from the front".

Mr. Speaker: All right.

श्री रामावतार शास्त्री : चीफ मिनिस्टर्स और फूड मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस में जिस नेशनल फूड बजट की चर्चा की गई थी क्या उस फूड बजट के तहत एक आदमी को एक साल में 128 किलोग्राम औसत अनाज देने की बात तय की गई है; यदि हां तो बिहार और केरल के लिये 110 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति साल क्यों रखा गया है ? उन को इतना कम देने की क्या वजह है ? क्या वहां के लोग औरों की अपेक्षा कम खाना खाते हैं ?

श्री जगजीवन राम : उस राष्ट्रीय खाद्य बजट को स्वीकार नहीं किया गया है इसलिये उसके आंकड़े यहां पर कोट करने से कोई लाभ नहीं निकलने वाला है ।

श्री वाल्मीकी चौधरी : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उन से प्रान्तों के खाद्य मंत्रियों अथवा मुख्य मंत्रियों से खाद्य सम्बन्धी बातचीत हुई है तो क्या वह आप की बातचीत से संतुष्ट होते हैं ? यदि हां तो फिर उन का वक्तव्य विपरीत क्यों होता है ? वैसे वक्तव्य के खंडन का कोई तरीका है या नहीं ?

Shri Annasahib Shinde: The policy is evolved as a result of the general consensus out of the discussions.

Some hon. Members *rose*—

Mr. Speaker: We shall go to the next question now.

भूख से मृत्यु

*152. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री धीरेन्द्र नाथ :
श्री प्र० के० देव :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री श्रद्धाकार सूपकार :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री यशपाल सिंह :
श्री न० कु० सांघी :
श्री पी० गोपालन :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री इब्राहिम :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री उमानाथ :
श्री एस्थोस :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री बेणीशंकर शर्मा :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री शारदा नन्द :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री रणजीत सिंह :
श्री ओंकार सिंह :
श्री रामसेवक यादव :
श्री म० म० प्रसाद :

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री वेंकोनम्बम पटोविया :
श्री मीठा लाल :
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :
श्री रा० बरुवा :
श्री चं० चु० देसाई :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री नाथूराम अहरवार :
श्री काशीनाथ पांडे :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से अप्रैल 1967 तक देश में राज्यवार कितने व्यक्ति के कहां कहां भूख से मरने के समाचार मि है ?

(ख) क्या सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये है जिस से इस प्रकार मौतें न हों ; और

(ग) यदि हां तो उनकी क्रियान्विति के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri D. Ering): (a) to (c). Statement is placed on the Table of the House.

STATEMENT

(a) All reports about starvation deaths whether appearing in newspapers or brought to the notice of the Government of India otherwise are referred by them to the State Governments for investigation and report. None of the reported starvation deaths has so far been confirmed by any of the State Governments.

(b) and (c). The State Governments have organised a large number of relief works in the affected areas in order to provide purchasing power for the people. For those unable to do hard manual work, light Manual schemes have also been organised. For old and infirm persons and others who cannot work to earn their livelihood, arrangements have been made to provide gratuitous relief in the form of cash and free supply of foodgrain and free kitchens are also being run by voluntary organisations to provide free food to such people. A large emergency feeding programme to cover vulnerable sections of the population namely children, expectant and nursing mothers has been organised by CARE. 23,500 tonnes of gift wheat and 12,000 tonnes of gift milk powder have so far been allotted to the affected States for gratuitous relief and for milk feeding programmes. 4,787 tonnes of wheat placed at the disposal of the Prime Minister's Drought Relief and 1,617 tonnes of wheat from Government stocks have been released to voluntary organi- tions for running free kitchens.

Government of India are extending necessary financial assistance to the State Governments for organising as many relief programmes as may be necessary. No ceiling has been laid for organising relief programmes. Allotment of allocations of foodgrains to the effected States has been increased to the extent possible in order to provide sufficient foodgrains in the fair price shops in the effected areas.

श्री ओंकार लाल बेरवा : वह स्टेटमेंट हमें नहीं मिला है इसलिए उसे पढ़ कर यहां सुनाया जाय ।

श्री शिव नारायण : प्वाइंट आफ आर्डर सर, स्टेमेंट बेरवा साहब के हाथ में है इसलिए हाउस में कहना कि स्टेमेंट नहीं मिला है ऐसा उनका कहना कहां तक जस्टिफाइड है ?

Mr. Speaker: In the previous question also this point was raised. But the statement laid on the Table in reply to this question has been received by several hon. Members. Others who have not got it may go and get it from the Table Office. What is the point of order in this? There is no point of order.

Shri Piloo Mody: Sir, I want to make one suggestion. Why not we do away with the lunch hour and convert the lunch hour also into a Question Hour so that we may have two hours?

Mr. Speaker: I have no objection... (*Interruptions*).

श्री ओंकार लाल बेरवा : इस स्टेटमेंट को देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि भारत सरकार पत्रकारों पर भी विश्वास नहीं करती और वहां की जो नौन कांग्रेस गवर्नमेंट्स हैं उन के मंत्रियों पर भी विश्वास नहीं करती लेकिन इस इन्तजार में है कि कांग्रेसी सज्जन रिपोर्ट भेजेंगे कि कोई भूख से मर गया तो उसे सच मानेंगे वरना कह देंगे कि भूख से कोई नहीं मरा। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के समाचार पत्रों के लोग इस बारे में उत्तर प्रदेश, बिहार, और राजस्थान सर्वे करने गये थे और वहां पर उन्होंने भुखमरी और भूख-मरी से हुई मौतों के बारे में जानकारी प्राप्त की भूख से मरने वालों के आंकड़े जो राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश की विधान सभाओं में बतलाये गये हैं वह आंकड़े मैं यहां पर बतलाना चाहता हूं। मध्यप्रदेश में भूख से 39 मरे, बिहार में 119 मरे, उत्तर प्रदेश में 65 मरे और राजस्थान में भूख से मरने वालों की संख्या 9 है। विज्ञान भवन में भी जो एक शो हुआ था उस में भी मरने वालों की संख्या को बतलाया गया था। ऐसी हालत में मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर भारत सरकार किस पर विश्वास करती है? जब उन विधान सभाओं में यह आंकड़े दे दिये गये हैं तो फिर आप को उनको स्वीकार करने में क्या आपत्ति है और क्या उन राज्यों ने अभी तक आप के पास वह रिपोर्टस नहीं भेजी हैं और क्या आप प्रैस वालों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जैसा कि प्रश्न के उत्तर में कहा गया है अखबारों में जो इस तरह के बयानात निकलते हैं कि वहां पर इतनी मृत्युएं हुईं अथवा जो कुछ भी समाचार हमारे मंत्रालय में आते हैं का जिन जिन राज्यों से सम्बन्ध होता है उन उन राज्यों को हम भेज देते हैं वह इस का पता लगा कर हमें सूचित करें कि सत्य क्या है और सम्बद्ध राज्य सरकारों से रिपोर्ट आती है उसी के आधार पर हम आप को सूचना दे सकते हैं। हमारी कोई अपनी एजेंसी नहीं इस बात की छानबीन करने की और जैसा कि विवरण में कहा गया है किसी भी राज्य सरकार ने अब तक भूख से हुई कथित मौत के बारे में पुष्टि नहीं की है

श्री ओंकार लाल बेरवा : जैसा कि अभी खाद्य मंत्री महोदय ने कहा कि उन की अपनी कोई इस के लिए अलग एजेंसी नहीं है और वह राज्य सरकारों से इस की जांच कराते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब उन विधान सभाओं में भूख से मरने वालों के आंकड़े दिये गये हैं और जब प्रधान मंत्री गई थीं तो उन को भी वहां पर दिखलाया गया था और सब बतलाया गया था तब फिर इस चीज को उसे स्वीकार करने में क्या आपत्ति है? अब सिनेमा भी झूठे, पत्रकार भी झूठे और यहां की विधान सभाएं भी झूठी तो सच्ची बात आखिर वह किस को मानते हैं?

श्री जगजीवन राम : राज्य सरकार से हम जांच कराते हैं और अगर वह उस को सही मानती है और हमें सूचित करती है तो उसको हम सच्ची बात मानते हैं।

श्री ओंकार लाल बेरवा : खाद्य मंत्री महोदय विधान सभाओं की बात क्यों नहीं मान रहे हैं? उन्होंने कबूल किया है कि वहां इतने इतने आदमी भूख से मरे हैं।

श्री जगजीवन राम : जैसा मैंने पहले कहा अगर राज्य सरकार हमें जांच करने के बाद यह लिख कर भेज दे कि उन के वहां भूख से मौतें हुई तो हम उस को मान लेते हैं।

Shri Virendrakumar Shah: I believe the Government is concerned

not only with starvation deaths but the likelihood of starvation deaths and so should take steps to avoid that. Is the Minister aware that the situation in Gujarat State in the districts of Panch Mahal, Chota Udaipur and Junagadh is such to lead to starvation deaths on a large scale? If so, what steps are the Government taking to see that adequate quantities of foodgrains are rushed to these areas in time?

Shri Jagjivan Ram: Yes, in certain areas of Gujarat there was failure of rain and drought conditions were prevailing. We released some foodgrains for free distribution in that area. Recently, the Chief Minister of Gujarat met me and requested me whether I will give him some more foodgrains for free distribution in the affected area. I am going to release 1,000 tons of wheat for free distribution amoung the adibasis.

Shri Sradhakar Supakar: Certain deaths on account of starvation were published in statements of some Ministers. Has the Government verified whether the Ministers actually made the statement or not?

Shri Annasahib Shinde: As already mentioned by the hon. Minister, we referred the statements to the various State Governments but no State Government has so far submitted any information which indicates that there have been deaths due to starvation.

12.00 hrs.

SHORT NOTICE QUESTIONS

Non-Payment of Money Orders

S.N.Q. No. 3. Shri K. N. Tiwary:
Shri Kartik Oraon:
Shri P. K. Ghosh:

Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) whether a large number of complaints were received in respect of non-payment of Money Orders throughout the country; and

(b) if so, how many have been paid and how many are still to be paid?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख) 15 मार्च से 15 मई, 1967 तक मनीआर्डर और तार मनीआर्डरों की अदायगी न होने के बारे में मुझे 92 शिकायतें मिली थी। इनमें से 32 की अदायगी पहले ही की जा चुकी है। शेष मनीआर्डरों और तार मनीआर्डरों की अदायगी की कार्यवाही की जा रही है। 1966 में 3,85,071 शिकायतें मिली थीं। इनमें से वर्ष के अन्त में केवल 40,586 शिकायतें अनिर्णीत रह गई थीं।

श्री क० ना० तिवारी: मैं जानना चाहता हूं कि जो बाकी शिकायतें हैं उन की जांच हो रही है या नहीं, और उन का निर्णय कब तक हो जायगा और पेमेन्ट कब तक हो हो जावेगा।

डा० राम सुभग सिंह: यह आदेश जारी किये जा रहे है कि जुलाई के अन्त तक पिछले वर्ष जितने मनी आर्डरों की अदायगी नहीं हुई है उन की अदायगी जरूर कर दी जाये।

श्री क० ना० तिवारी: जितने मनीआर्डर लोगों ने किये उन की रकम क्या थी और उस में से कितने रुपयों का पेमेन्ट हुआ है और कितने का नहीं हुआ है?

डा० राम सुभग सिंह: असल में वर्ष भर में करीब 9 करोड़ 20 लाख मनीआर्डर आते जाते हैं जिन के लिये 4,420 मिलियन रुपयों का ऐवरेज है। यह बड़ी रकम है, लेकिन जो शिकायतें मिली हैं उन की ऐवरेज 3,47,500 है जो कि .4 परसेंट होता है।

Shri Kartik Oraon: I would like to know from the Minister the number of money orders and the amount involved in them in respect of Bihar,